डिजिटल पेमेंट करने वाले कामगारों को ब्याज में सब्सिडी देने की तैयारी

अमर उजाला ब्यूरो

सीएम बोले- छोटे उद्यम रोजगार के बड़े स्रोत, इनकी स्थापना भी आसान

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि छोटे-छोटे उद्यमों को स्थापित करना ज्यादा आसान है क्योंकि उनके लिए न तो जमीन का अधिग्रहण करना पड़ता है और न ही भारी भरकम पूंजी की जरूरत पड़ती है। ये रोजगार भी सबसे ज्यादा देते हैं। छोटी पूंजी कभी डूबती नही है। सीएम ने एमएसएमई मंत्री राकेश सचान के सुझाव को स्वीकार करते हुए कहा कि कामगारों को डिजिटल पेमेंट के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि वे कर्ज वापसी के लिए आगे बढ़ें। इन्हें ब्याज में सब्सिडी देने का भी विचार है। वे शनिवार को लोकभवन में हुए विश्वकर्मा श्रम सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि सभी 58 हजार ग्राम पंचायतों में हाट बनाएंगे जहां सभी विधाओं की दुकान होंगी। बिना क्लस्टर के कोई भी उद्यम तब तक सफल नहीं हो सकता है, जब तक एमएसएमई का बेहतरीन क्लस्टर उसके पास न हो। प्रदेश इस नजरिए से सौभाग्यशाली है क्योंकि यहां एमएसएमई की 96 लाख से ज्यादा इकाइयां हैं। उन्होंने डेबिट क्रेडिट अनुपात को 55 फीसदी से 60-62 फीसदी ले जाने के लिए बैंकों से आह्वान किया। कार्यक्रम में सीएम ने विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना और ओडीओपी योजना के कुछ लाभार्थियों को प्रतीकात्मक तौर पर टूल किट दिए।

एमएसएमई उद्यमियों को ऋण भी वितरित किया। इस दौरान एमएसएमई मंत्री राकेश सचान, मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र, अवस्थापना और औद्योगिक विकास आयुक्त मनोज कुमार सिंह, क्षेत्रीय निदेशक भारतीय रिजर्व बैंक डॉ बालू केंचप्पा, अपर मुख्य सचिव एमएसएमई अमित मोहन प्रसाद, एसएलबीसी प्रमुख समीर रंजन पांडा और एसबीआई के सीजीएम शरद चांडक भी मौजूद थे।

मुख्यमंत्री योगी ने शनिवार को राजभवन में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से शिष्टाचार भेंट की। स्रोत : सूचना विभाग

कर्ज का बोझ घटाने के लिए दे सकते हैं सब्सिडी

अन्य योजनाओं की तरह विश्वकर्मा योजना में भी लोन लेने वाले परंपरागत कामगारों को ब्याज में सब्सिडी देने पर राज्य सरकार विचार कर रही है। एमएसएमई मंत्री राकेश सचान ने बताया कि विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना का लक्ष्य कम पूंजी में ज्यादा लोगों को रोजगार देना है। परंपरागत काम करने वाले हुनरमंदों के कौशल को इसीलिए निखारा जा रहा है ताकि उन्हें तीन लाख रुपये तक का लोन देकर आत्मनिर्भर बनाया जा सके। लोन पर सब्सिडी देने का भी विचार है, क्योंकि लोन देते ही कामगार को पहले दिन से मुनाफा नहीं होने लगेगा। ब्याज में कितनी सब्सिडी दी जाए, इसका फैसला जल्द लिया जाएगा। इसका प्रस्ताव मुख्यमंत्री को दिया है ताकि छोटे कामगारों को बड़ा प्रोत्साहित किया जा सके।